

लंबित राजस्व वादों में देरी पर जवाबदेह होंगे : सीएम

कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिलों की जवाबदेही तय की जाये, 22 लाख से घटकर 10 लाख हुए लंबित वाद

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि राजस्व मामलों के त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि और राजस्व से जुड़े विवाद आमजन के जीवन, किसान हितों और सामाजिक सौहार्द से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए इन मामलों में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्धारित समय-सीमा के बाद भी लंबित रहने वाले मामलों में संबंधित अधिकारियों और कार्मिकों की जवाबदेही तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

शनिवार को राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण की प्रगति की रूच्वस्तरीय समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक आधारित व्यवस्था, जवाबदेही और समयबद्ध कार्यप्रणाली के माध्यम से राजस्व न्यायालयों की



● **धारा-80 के लंबित वाद 85 हजार से घटकर 38 हजार, राजस्व मामलों में तेजी पर जोर**

कार्यक्षमता को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, ताकि आम नागरिक को शीघ्र न्याय मिल सके। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि निर्धारित समय-सीमा से अधिक अवधि से लंबित वादों का अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि तहसीली और जनपद स्तर पर नियमित समीक्षा हो तथा कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिलों की जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री

संख्या में भी लगातार कमी आई है। धारा-80 के मामलों में बस्ती, चित्रकूट, अयोध्या, बागपत और कन्नौज ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि मेरठ, वाराणसी, अमेठी, गौतमबुद्धनगर और हापुड़ का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर पाया गया।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि धारा-34 के अंतर्गत लंबित वादों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। 1 जनवरी 2026 को कुल 22,44,466 वाद लंबित थे, जो 22 मई 2026 तक घटकर 10,59,139 रह गए। इस अवधि में 5,40,945 वादों का निस्तारण किया गया।

समीक्षा में बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ और बदायूं का प्रदर्शन बेहतर पाया गया, जबकि गोरखपुर, संतकबीरनगर, प्रतापगढ़, बलिया और देवरिया अपेक्षित प्रगति नहीं कर सके। मुख्यमंत्री ने इन जिलों में विशेष अभियान चलाकर लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। धारा-33 के अंतर्गत निर्विवादित वरासत मामलों की समीक्षा में

बताया गया कि वर्ष 2025 में कुल 16,89,732 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 16,43,104 का निस्तारण किया गया। वहीं 22 मई 2026 तक प्राप्त 7,15,872 आवेदनों में से 6,52,512 का निस्तारण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वरासत से जुड़े मामलों में नागरिकों को अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें तथा सभी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में धारा-24 के मामलों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 1 जनवरी 2026 को 1,82,710 वाद लंबित थे, जो 22 मई 2026 तक घटकर 92,915 रह गए। समीक्षा में वाराणसी, कुशीनगर, मैनपुरी, बलरामपुर और हमीरपुर का प्रदर्शन बेहतर पाया गया, जबकि गौतमबुद्धनगर, लखनऊ, प्रतापगढ़, अमेठी और मुजफ्फरनगर अपेक्षित प्रगति नहीं कर सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में प्रगति संतोषजनक नहीं है, वहां वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्रशासन की कार्यशैली ऐसी होनी चाहिए, जिससे जनता का विश्वास और अधिक मजबूत हो तथा लोगों को न्याय के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े।

उप्र मदरसा बोर्ड का रिजल्ट घोषित, 88.26% छात्र-छात्राएं उत्तीर्ण

मदरसा बोर्ड परीक्षा में 55,788 छात्र-छात्राएं सफल, छात्राओं का प्रदर्शन सबसे बेहतर

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा को आधुनिक, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में योगी सरकार लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। इसी क्रम में शनिवार को उप्र मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संचालित मुंशी/मौलवी (सेकेंडरी) तथा आलिम (सीनियर सेकेंडरी) बोर्ड परीक्षा वर्ष-2026 का परिणाम घोषित किया गया। इस वर्ष मदरसा बोर्ड परीक्षा का कुल परिणाम 88.26 प्रतिशत रहा। कुल 55,788 छात्र-छात्राएं सफल घोषित किए गए। खास बात यह रही कि छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। कुल 29,229 छात्राएं 94.30 प्रतिशत सफलता दर के साथ पास हुईं, जबकि 26,559 छात्र 85.13 प्रतिशत दर के साथ सफल हुए।

सेकेंडरी यानी मुंशी-मौलवी परीक्षा में कुल 62,232 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 47,036 छात्र-



● **सेकेंडरी में 41 हजार से ज्यादा परीक्षार्थी पास, सीनियर सेकेंडरी में भी बेटीयों का दबदबा**

छात्राओं ने परीक्षा दी, जिनमें 41,426 परीक्षार्थी सफल रहे। इस परीक्षा का कुल परिणाम 88.07 प्रतिशत रहा। सेकेंडरी में भी छात्राओं का प्रदर्शन शानदार रहा है। 21,407 छात्राएं 91.46 प्रतिशत सफलता दर के साथ पास हुईं, जबकि 20,019 छात्र 84.72 प्रतिशत अंक के साथ सफल घोषित किए गए।

वहीं, सीनियर सेकेंडरी यानी आलिम परीक्षा में कुल 18,701 छात्र-छात्राएं पंजीकृत थे। इनमें से 16,175

उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी चेतावनी प्रणाली

मुख्यमंत्री योगी ने दिए त्वरित और जनकेद्रित मौसम अलर्ट के निर्देश

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में मौसम संबंधी पूर्व चेतावनी प्रणाली को और अधिक सटीक, त्वरित तथा जनकेद्रित बनाने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को राहत एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समय पर दी गई सही सूचना अनेक लोगों का जीवन बचा सकती है। इसलिए मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी तंत्र को केवल तकनीकी व्यवस्था तक सीमित न रखते हुए अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने गांवों और संवेदनशील क्षेत्रों में हल्लास्ट माइल कर्नेक्टिविटीहम मजबूत करने, आईबीआरएस, पंचायत स्तर के लाउडस्पीकर, स्थानीय एफएम रेडियो, मोबाइल अलर्ट तथा सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग करने के निर्देश दिए।

बैठक में 13 मई 2026 को आए भीषण आंधी-तूफान की समीक्षा प्रस्तुत की गई। बताया गया कि आईएमडी के मल्टी-हैजार्ड अली वर्निंग सिस्टम (एमएसईडब्ल्यूएस) द्वारा इस घटना की सात दिन पहले से निगरानी की जा रही थी। प्रारंभ में येलो वर्निंग जारी की गई, जिसे बाद में ऑरेंज वर्निंग तथा कई जिलों में रेड अलर्ट में अपग्रेड किया गया। चेतावनियों

भाजपा पीडीए का आरक्षण खा गयी

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने पीडीए आरक्षण में घोटाला किया है। भाजपा पीडीए का आरक्षण खा गयी। 69 हजार शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्गों को 27 फीसदी आरक्षण के बजाय सिर्फ 3.80 फीसदी आरक्षण मिला। एससी वर्ग को 21 फीसदी आरक्षण की जगह 16.2 फीसदी आरक्षण मिला। भाजपा सरकार ने पिछड़े, दलितों के आरक्षण को लूट की है। भाजपा निजीकरण करके आरक्षण को समाप्त करने की साजिश कर रही है। युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।

पाटी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में विभिन्न जिलों से आये कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सुविधा, सम्मान, आरक्षण और सामाजिक न्याय का राज समाजवादी पार्टी की सरकार में ही सम्भव है। उन्होंने कहा कि सपा की स्थापना का लक्ष्य ही तमाम तरह की विषमता को मिटाना है। भाजपा की आर्थिक नीतियों से



विषमता बढ़ी थी। भाजपा ने अमीरी-गरीबी की खाई को बढ़ाकर आर्थिक केन्द्रीकृत किया। यह भ्रष्टाचार का तरीका है। भारत की आर्थिक ताकत कुछ हाथों में संग्रहित की जा रही है। महंगाई से आम जन तबाह है। देश के करोड़ों बेरोजगारों को कोई पूछने वाला नहीं है। भाजपा सरकार जनता के लिए नहीं बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों के हित में काम करती है।

भाजपा ने चंद पूंजीपतियों के लिए किसानों की किस्मत गिरवी रख दी है। भाजपा गरीबों, किसानों के लिए काम नहीं करती है बल्कि भाजपा गरीबों और किसानों की दुश्मन है। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए पाटी के सभी नेताओं की सामूहिक

जिम्मेदारी है। सपा के कार्यकर्ता और बूध ग्रहरी सतर्क रहे। भाजपा अभी भी मतदाता सूची में हेराफेरी की साजिश कर सकती है। भाजपा राजनीति को गैर बनाकर काम कर रही है। चौतरफा लूट मचा रखी है। लूट की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि पाटी कार्यकर्ताओं की भाषा व्यवहार ऐसा हो जिससे किसी को शिकायत का मौका न मिल सके।

पिछले साल के मुकाबले कम सड़क हादसे, मृतकों की संख्या घटी

इस अवधि में सड़क दुर्घटनाओं में 21 और मृत्यु में 22 प्रतिशत की कमी की गई दर्ज

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद संजीदा हैं। हादसों को न्यूनतम करने की दिशा में वे समय-समय पर संबंधित विभागों की समीक्षा, सकारात्मक प्रयास, जागरूकता आदि पर जोर देते हैं। लिहाजा, सड़क सुरक्षा को लेकर योगी सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। ई-2025आर पोर्टल के मुताबिक, वर्ष 2025 की जनवरी से अप्रैल की समयावधि की अपेक्षा जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 के बीच दुर्घटनाओं और इससे होने वाली मृत्यु में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। इस अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में 3669 (21 प्रतिशत) दुर्घटनाएं कम हुईं हैं, जबकि मृतकों की संख्या में भी 2212 (22 प्रतिशत) की कमी दर्शाई गई है।



सीएम के निर्देश के उपरांत सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए लगभग 2000 स्थानों पर होर्डिंग लगाई गई और प्रचार-प्रसार के जरिए परिवहन विभाग आमजन को निरंतर जागरूक भी कर रहा है।

सीएम योगी के निर्देश पर परिवहन निगम के चालकों की निरंतर स्वास्थ्य/नेत्र जांच की जा रही है। हर छमाही चेकअप किया जा रहा है। अप्रैल 2026 तक 18,975 वाहन चालकों का स्वास्थ्य परीक्षा किया जा चुका है। शेष 2560 चालकों की जांच भी

चल रही है। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत यूपीएसआरटीसी की बसों पर रेडो रिफ्लेक्टर टेप लगाया जा चुका है। ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण अनिवार्य किया गया है। वहीं 300 किमी. से अधिक यात्रा वाली बसों में दो चालक की ड्यूटी भी अनिवार्य की गई है। सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग/निगम काफी संजीदगी से प्रयासों को धरातल पर उतार रहा है। सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि को न्यूनतम करने के उद्देश्य से केंद्रीय सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार

द्वारा उत्तर प्रदेश के 20 जनपदों के 242 क्रिटिकल थानों को जीरो फ़ैटेलिटि योजना के लिए चिह्नित किया गया था। यातायात निदेशालय के मुताबिक इस योजना के क्रियान्वयन के उपरांत 4 महीने में 566 व्यक्तियों की जान बचाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 487 क्रिटिकल पुलिस थानों पर यह योजना लागू की गई है। इन 487 क्रिटिकल थानों में 573 क्रिटिकल कंरिडोर टीम गठित की गई है। हर टीम में एक उपनिरीक्षक व 4 मुख्य अरक्षी/आरक्षी (2865

पुलिसकर्मी) नियुक्त हैं, जो जीरो फ़ैटेलिटि को सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। पहली जनवरी 2026 से 15 मई 2026 के बीच सभी 18 मंडलों में होल्डिंग एरिया भी चिह्नित व नोटिफाइड किए गए। मंडलों में 656 होल्डिंग एरिया चिह्नित किए गए, इसमें से 630 को नोटिफाइड भी किया गया। आगरा मंडल में सर्वाधिक 121, बरेली में 103, मुरादाबाद में 75, आजमगढ़ में 62 होल्डिंग एरिया चिह्नित/नोटिफाइड किए गए हैं।

द्वारा उत्तर प्रदेश के 20 जनपदों के 242 क्रिटिकल थानों को जीरो फ़ैटेलिटि योजना के लिए चिह्नित किया गया था। यातायात निदेशालय के मुताबिक इस योजना के क्रियान्वयन के उपरांत 4 महीने में 566 व्यक्तियों की जान बचाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 487 क्रिटिकल पुलिस थानों पर यह योजना लागू की गई है। इन 487 क्रिटिकल थानों में 573 क्रिटिकल कंरिडोर टीम गठित की गई है। हर टीम में एक उपनिरीक्षक व 4 मुख्य अरक्षी/आरक्षी (2865

जून माह में नहीं करायी जायें सेमेस्टर परीक्षाएं

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी शिक्षक प्रकोष्ठ के चेयरमैन ने सीएम योगी और राज्यपाल को पत्र लिखकर उठायी मांग



आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अनेक महाविद्यालयों में पंखे एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं भी सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रही हैं। ऐसी स्थिति में भीषण गर्मी के बीच परीक्षा कराना छात्रों एवं शिक्षकों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रीष्मवर्षाकाश के दौरान परीक्षाएं आयोजित करना किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है।

डॉ. अमित कुमार राय ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि छात्रों एवं शिक्षकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तत्काल संवेदनशील निर्णय लिया जाए।

उप्र मद्रसा बोर्ड का रिजल्ट घोषित, 88.26% छात्र-छात्राएं उत्तीर्ण

मदरसा बोर्ड परीक्षा में 55,788 छात्र-छात्राएं सफल, छात्राओं का प्रदर्शन सबसे बेहतर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा को आधुनिक, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में योगी सरकार लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। इसी क्रम में शनिवार को उप्र मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संचालित मुंशी/मौलवी (सेकेंडरी) तथा आलिम (सीनियर सेकेंडरी) बोर्ड परीक्षा वर्ष-2026 का परिणाम घोषित किया गया। इस वर्ष मदरसा बोर्ड परीक्षा का कुल परिणाम 88.26 प्रतिशत रहा। कुल 55,788 छात्र-छात्राएं सफल घोषित किए गए। खास बात यह रही कि छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। कुल 29,229 छात्राएं 94.30 प्रतिशत सफलता दर के साथ पास हुईं, जबकि 26,559 छात्र 85.13 प्रतिशत दर के साथ सफल हुए।

सेकेंडरी यानी मुंशी-मौलवी परीक्षा में कुल 62,232 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 47,036 छात्र-

मदरसा बोर्ड परीक्षा में 55,788 छात्र-छात्राएं सफल, छात्राओं का प्रदर्शन सबसे बेहतर

प्रदेश सरकार द्वारा पीएम पोषण योजना में गुणवत्ता और स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। भोजन की नियमित मॉनिटरिंग के साथ-साथ रसोइयों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। स्वच्छ भोजन निर्माण, पोषण संतुलन और खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है।

रसोई से मंच तक पहुंची वतिभा : योगी प्रदेश सरकार रसोइयों को भोजन तैयार करने वाली कार्यकर्ता से आगे बढ़कर 'पोषण प्रहरी' के रूप में पहचान दे रही है। इसी उद्देश्य से विभिन्न जनपदों में हारमोशिया पक-कला

प्रतियोगिताओंका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 3500 रुपये, द्वितीय 2500 रुपये एवं तृतीय पुरस्कार 1500 रुपये के अलावा प्रतिभाग करने वाली सभी रसोइयों को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वाराणसी में आयोजित पक-कला प्रतियोगिता में रसोइयों ने स्वाद, स्वच्छता और पौष्टिकता के उत्कृष्ट समन्वय का प्रदर्शन किया। विजेता प्रतिभागियों

को सम्मानित कर सरकार ने यह संदेश दिया कि बच्चों के भविष्य को संवारने वालों का सम्मान सर्वोपरि है।

पोषण से विकसित उत्तर प्रदेश का मजबूत संकल्प : पीएम पोषण योजना आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी मॉडल बन चुकी है। यह योजना बच्चों को बेहतर पोषण, नियमित शिक्षा और सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के विद्यार्थी बच्चे तक बेहतर पोषण, प्रत्येक विद्यालय तक गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं और प्रत्येक परिवार तक शिक्षा व्यवस्था के प्रति विश्वास को मजबूत किया जाए। इसी उद्देश्य के अंतर्गत विद्यालयों में पोषण, गुणवत्ता और आधुनिक संसाधनों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। आज विद्यालयों की थालियों में परोसा जा रहा भोजन केवल अनन नहीं, बल्कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य का मजबूत संकल्प बन चुका है।

बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि संबंधित इकाइयों स्थानीय कृषकों से प्राथमिकता के आधार पर कच्चे माल की खरीद सुनिश्चित करें। साथ ही, निवेशकों को फायर सेफ्टी, प्रसूषण नियंत्रण एवं अन्य आवश्यक तकनीकी अनापूर्तिासक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करनी होंगी। अपर मुख्य सचिव बीएल मीणा ने कहा कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से कृषि आधारित उद्योगों को गति मिलेगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बैठक में विभागीय अधिकारियों एवं तकनीकी विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया।

